हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 15 फ़रवरी 2026, समय 1305 (5 मिनट)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के विभिन्न जिलों के लिए 18 हजार 509 करोड़ रुपए की तीन मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इससे रेल अवसंरचना मजबूत होगी, लॉजिस्टिक लागत कम होगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इन परियोजनाओं में कसारा-मनमाड, दिल्ली-अंबाला और बल्लारी-होसापेटे के बीच तीसरी और चौथी लाइनों का निर्माण शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि लाइन क्षमता में वृद्धि से गतिशीलता में काफी वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे के लिए परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा।

प्रधानमंत्री ने सडक दुर्घटना में घायलों को अस्पताल में भर्ती और उन्हें इलाज की गारंटी देने के लिए पीएम राहत योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना में किसी भी तरह की सडक पर दुर्घटना की स्थिति में सात दिन तक के इलाज के लिए डेढ लाख रुपये तक के नकदी रहित इलाज का खर्च सरकार उठायेगी। मंत्रालय के अनुसार, सरकार अस्पतालों को मोटर वाहन दुर्घटना कोष से भुगतान करेगी।

रेलवे में अब सामान्य श्रेणी के यानी जनरल कोच की सफाई भी फर्स्ट क्लास कोच की ही तरह की जाएगी। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में बताया कि इस पहल के तहत शुरूआत में, छह महीने के भीतर लम्बी दूरी की अस्सी

रेलगाडियों की पहचान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन रेलगाडियों में एक से डेढ घंटे के अंतराल पर सफाई के लिए अलग से कर्मचारी रखे जायेंगे।

जो ट्रेन्स हमारी चलती है लॉन्ग डिस्टेंस, स्पेशली उनका प्रॉपर एंड टू एंड क्लीनिंग हो सके। दूसरा स्टेशन पे एक क्लिन ट्रेन स्टेशन का कॉन्सेप्ट बना है। कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेशंस पे पूरी थोरो क्लीनिंग करने का अभी करंट सिस्टम है। इसके बजाए, ट्रेन के ओरिजिन से लेके ट्रेन के डेस्टिनेशन तक, कंटीन्यूअसली ट्रेन की क्लीनिंग हो।

देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय परिसरों के निर्माण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के नए भवन का निर्माण किया जा रहा है।तीन चरणों में निर्मित किए जा रहे नए भवन में 34 नए न्यायालय कक्ष बनाए जा रहें हैं, जो आगामी 50 वर्ष की व्यवस्था के लिए पर्याप्त होंगे। वे कल रोहतक के न्यायिक परिसर में जिला बार एसोसिएशन द्वारा देश के मुख्य न्यायाधीश के सम्मान में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्यातिथि न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं को संबोधित कर रहे थे।

न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत ने सरकार व जिला बार एसोसिएशन से कहा कि वे भी भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक परिसर बनाने पर विचार करें। उन्होंने बार एसोसिएशन की ओर से रखी मांग के संदर्भ में कहा कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा भवन समिति के अध्यक्ष रोहतक बार की समस्या का कानून की मर्यादा का पालन करते हुए समाधान करवाये। उन्होंने रोहतक बार के साथ अपने भावनात्मक गहरे नाते का जिक्र करते हुए रोहतक से जुड़े अपने निजी अनुभव भी साझा किए। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया और स्मृति चिन्ह भेंट किया। जिला एवं सत्र मंडल के प्रशासनिक न्यायाधीश विकास सूरी और उपायुक्त सचिन गुप्ता द्वारा भी मुख्य न्यायाधीश को सम्मानित किया गया। वकीलों द्वारा मुख्य न्यायाधीश को भेंट किये गए उनके चित्र पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने

हस्ताक्षर किए, जिसे बार रूम में रखा जायेगा। जिला बार एसोसिएशन रोहतक द्वारा पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू ,हरियाणा उच्च न्यायालय की भवन समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी तथा प्रशासनिक न्यायाधीश विकास सूरी और सहकारिता एवं कारागार मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा को भी स्मृतिचिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

आज महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरी श्रद्धा और धार्मिक मान्यताओं के साथ मनाया जा रहा है।

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। लोग शिवलिंग पर जल वो अन्य सामग्री अर्पित कर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं।

करनाल की हुड्डा ग्राउंड में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 10 दिवसीय राज्य स्तरीय खादी महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत कारीगरों को टूलकिट वितरित की गई। कार्यक्रम में 206 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया गया। महोत्सव में चरखा चलाने, मिट्टी के बर्तन बनाने और अगरबत्ती तैयार करने के लाइव डेमो प्रस्तुत किए गए, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इन प्रस्तुतियों ने न केवल पारंपरिक कौशल को जीवंत किया, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित भी किया।

हरियाणा खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि खादी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कारीगरों और ग्रामीण उद्योगों को एक मंच देना है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के निरंतर जमीन उपलब्ध करवाई जा रही है और अलग-अलग औद्योगिक जोन बनाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार 10 नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप -आईएमटी भी बना रही है। मुख्यमंत्री ऐसी कंपनियों के प्रतिनिधियों से को संबोधित कर रहे थे जो हरियाणा में उद्योंगों के लिए जमीन तलाश कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विश्वभर की कंपनियां अलग-अलग देशों में काम कर रही हैं। ऐसे में वैश्विक सामर्थ्य केंद्रों - जी सी सी का रूझान तेजी से बढ़ा है। प्रदेश सरकार जल्द ही जी सी सी के लिए नई नीति ला रही है। इससे ऐसी कंपनियों को आसानी होगी, जो हरियाणा में जीसीसी स्थापित करना चाहती है।